भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3297

उत्तर देने की तारीख- 16/12/2024

उच्च शिक्षा पर व्यय को बढ़ाना

†3297. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेष रूप से राजस्थान में, विभिन्न स्तरों पर उच्च शिक्षा के वित्तपोषण से संबंधित वित्तीय चुनौतियों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी अनदेखी के क्या कारण हैं;

(ख) सभी छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा की वित्तीय स्थिरता और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से राजस्थान में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार देश भर में और विशेष रूप से राजस्थान में इस क्षेत्र में वित्तपोषण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वर्तमान व्यय स्तर को बनाए रखने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदर)

(क से ग) शिक्षा, समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। भारत सरकार उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा में अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। पीएम ऊषा के तहत, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के चयनित लोक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में शुरू की गई पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा न बनें। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना की गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है।

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	वित्तीय वर्ष: 2022-23	वित्तीय वर्ष: 2023-24	वित्तीय वर्ष: 2024-25
32,900	36031.57	40828.35	44744.48	47619.77

उच्चतर शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2875.29 करोड़ रुपये की समग्र वृद्धि हुई है।

राजस्थान में तीन केंद्रीय वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों, अर्थात् आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर और सीयू राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30.11.2024 तक कुल 556.86 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान राज्य में आईआईएम उदयपुर और आईआईआईटी कोटा की स्थापना के लिए 535.99 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

*****